



महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग सात

वर्ष ५, अंक १८]

गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २९-सप्टेंबर ४, २०१९/भाद्र ७-१३, शके १९४१

[पृष्ठ २८

किंमत : रुपये ३७.००

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

अनुक्रमणिका

	पृष्ठे
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५४, सन २०१७.— महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता और महाराष्ट्र भू-राजस्व (भूमि के उपयोग का संपरिवर्तन और अ-कृषक निर्धारण) नियम (संशोधन) अधिनियम, २०१७।	२
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५५, सन २०१७.— महाराष्ट्र लोक न्यास (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१७।	५
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५६, सन २०१७.— महाराष्ट्र विधानमंडल सदस्य (निरर्हता को हटाना) (संशोधन) अधिनियम, २०१७।	१३
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५७, सन २०१७.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१७।	१५
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५८, सन २०१७.— महाराष्ट्र धृति का खण्डकरण और समेकन की रोकथाम (संशोधन) अधिनियम, २०१७।	२५
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५९, सन २०१७.— महाराष्ट्र स्टाम्प (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१७।	२७
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६०, सन २०१७.— महाराष्ट्र भू-राजस्व (तृतीय संशोधन) अधिनियम, २०१७।	२८

MAHARASHTRA ACT No. LIV OF 2017.

THE MAHARASHTRA LAND REVENUE CODE AND THE
MAHARASHTRA LAND REVENUE (CONVERSION OF USE OF LAND
AND NON-AGRICULTURAL ASSESSMENT) RULES, (AMENDMENT)
ACT, 2017.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक ३१ अगस्त २०१७
को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

नि. ज. जमादार,
प्रधान सचिव एवं विधि परामर्शी,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. LIV OF 2017.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA LAND
REVENUE CODE, 1966 AND THE MAHARASHTRA LAND REVENUE
(CONVERSION OF USE OF LAND AND NON-AGRICULTURAL
ASSESSMENT) RULES, 1969.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५४, सन् २०१७।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, “महाराष्ट्र राजपत्र ” में दिनांक १ सितम्बर २०१७
को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ और महाराष्ट्र भू-राजस्व (भूमि के उपयोग का संपरिवर्तन
और अ-कृषक निर्धारण) नियम, १९६९ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ और महाराष्ट्र भू-राजस्व सन् १९६६
(भूमि के उपयोग का संपरिवर्तन और अ-कृषक निर्धारण) नियम, १९६९ में अधिकतर संशोधन करना का महा.
इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता ४१।
हैं, अर्थात् :-

अध्याय एक

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम। १. (१) यह अधिनियम, महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता और महाराष्ट्र भू-राजस्व (भूमि के उपयोग का संपरिवर्तन
और अ-कृषक निर्धारण) नियम (संशोधन) अधिनियम, २०१७ कहलाए।

अध्याय दो

महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ में संशोधन।

सन् १९६६ का ४१ २. महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ (जिसे इसमें आगे, “ उक्त संहिता ” कहा गया हैं) की धारा सन् १९६६
की धारा ११३ में ११३ की, उप-धारा (२ग) के स्थान में, निम्न उप-धारा रखी जायेगी, अर्थात् :- का ४१।
संशोधन।

“(२ग) उप-धारा (१) या तद्धीन बनाये गये नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, १ अगस्त, २००१ के पश्चात्, प्रत्येक गारंटी दिये गये पाँच वर्षों की अवधि के लिये अ-कृषक निर्धारण का दर, ऐसे गारंटी अवधि (जिसे इसमें आगे, “संदर्भ दिन” कहा गया है) के प्रारंभ से सद्य अनुवर्ती दिन पर वर्तमान दर से कम नहीं होगा और,—

(क) अ-कृषक प्रयोजनों के लिये जो पहले से ही निर्धारित है मामलों के लिये, नगर निगम क्षेत्र में, संदर्भ दिनांक पर वर्तमान अ-कृषक निर्धारण दर के तीन गुना और राज्य के शेष क्षेत्र में, ऐसे दर के दो गुना ; और

(ख) अ-कृषक प्रयोजनों के लिये निर्धारित किये जाने वाले मामलों के लिये, नगर-निगम क्षेत्र में, संदर्भ दिन पर प्रचलित अ-कृषक निर्धारण दर के छह गुना और राज्य के शेष क्षेत्र में चार गुना से अधिक नहीं होगा । ” ।

अध्याय तीन

महाराष्ट्र भू-राजस्व (भूमि के उपयोग का संपरिवर्तन और अ-कृषक निर्धारण)

नियम, १९६९ में संशोधन।

३. महाराष्ट्र भू-राजस्व (भूमि के उपयोग का संपरिवर्तन और अ-कृषक निर्धारण) नियम, १९६९ (जिसे इसमें आगे “उक्त नियम” कहा गया है) के नियम १५ के स्थान में, निम्न नियम, रखा जायेगा और १ अगस्त १९९६ से रखा गया समझा जायेगा।

महाराष्ट्र भू-राजस्व (भूमि के उपयोग का संपरिवर्तन और अ-कृषक निर्धारण)

“१५. संपूर्ण बाजार मूल्य कैसे निर्धारित किया गया.— ब्लॉक के नगरीय क्षेत्र में अ-कृषक भूमियों का संपूर्ण बाजार मूल्य सद्य पूर्ववर्ती वर्ष जिसमें अ-कृषक निर्धारण के मानक दर नियत किये जानेवाले हैं जो महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम के अधीन विरचित बम्बई स्टाम्प (सम्पत्ति के सही बाजार मूल्य का अवधारण)

नियम, १९६९ के नियम १५ का प्रतिस्थापन।

नियम, १९९५ के अधीन मुख्य नियंत्रण राजस्व प्राधिकारी द्वारा दरों के वार्षिक विवरण के प्ररूप में यथा अवधारित या जारी किए गए भूमि दरों के आधार पर अनुमानित किया जाएगा।”।

४. उक्त नियमों के नियम १६ के उप-नियम (३) में, “३.०० प्रतिशत” अंकों और शब्दों के स्थान में, “०.०५ प्रतिशत” अंक और शब्द रखे जायेंगे और १ अगस्त, १९९६ से रखे गये समझे जायेंगे।

महाराष्ट्र भू-राजस्व (भूमि के उपयोग का संपरिवर्तन और अ-कृषक निर्धारण) नियम, १९६९ के नियम १६ में संशोधन।

अध्याय चार

विविध।

५. किन्हीं भी परिस्थितियों के अधीन, कोई भी व्यक्ति, महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता और महाराष्ट्र भू-राजस्व (भूमि के उपयोग का संपरिवर्तन और अ-कृषक निर्धारण) नियम (संशोधन) अधिनियम, २०१७ के प्रारंभण के दिनांक से पूर्व, महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ के उपबंधों के अधीन किये गये किसी निर्धारण के लिये भुगतान की गई किसी रकम के प्रतिदाय के लिये हकदार नहीं होगा ।

संहिता के अधीन प्रतिदाय नहीं होगा।

६. (१) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ या यथास्थिति, महाराष्ट्र भू-राजस्व (भूमि के उपयोग का संपरिवर्तन और अ-कृषक निर्धारण) नियम, १९६९ के उपबंधों को प्रभावी बनाने में, यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है, तो, राज्य सरकार, जैसा अवसर उद्भूत हो, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, उक्त संहिता और उक्त नियमों के उपबंधों से अनसंगत हो, ऐसे कार्य कर सकेगी, जो उसे कठिनाई के निराकरण के प्रयोजन के लिये, आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो :

कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति।

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग सात, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २९-सप्टेंबर ४, २०१९/भाद्र ७-१३, शके १९४१

परन्तु, इस अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के पश्चात्, ऐसा कोई आदेश नहीं बनाया जायेगा ।

(२) उप-धारा (१) के अधीन, बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाये जाने के पश्चात्, यथासंभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा ।

(यथार्थ अनुवाद),

हर्षवर्धन जाधव,

भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य ।

MAHARASHTRA ACT No. LV OF 2017.

**THE MAHARASHTRA PUBLIC TRUST (SECOND AMENDMENT)
ACT, 2017.**

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक ३१ अगस्त, २०१७ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

नि. ज. जमादार,
प्रधान सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. LV OF 2017.

**AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA PUBLIC
TRUST ACT.**

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५५, सन् २०१७।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, “महाराष्ट्र राजपत्र” में दिनांक १ सितम्बर, २०१७ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र लोक न्यास अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम।

सन् १९५० का २९। **क्योंकि** इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र लोक न्यास अधिनियम में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; इसलिये, भारत गणराज्य के अडसठवें वर्ष में, एतद्वारा, निम्न अधिनियम, अधिनियमित किया जाता है :-

१. (१) यह अधिनियम, महाराष्ट्र लोक न्यास (द्वितीय संशोधन) अधिनियम कहलाए।

संक्षिप्त नाम तथा
प्रारंभण।

(२) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, नियत करें।

सन् १९५० का २९। २. महाराष्ट्र लोक न्यास अधिनियम (जिसे इसमें आगे, “मूल अधिनियम” कहा गया है) की धारा २ में,—
(क) खण्ड (२) के पश्चात्, निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :-

सन् १९५० का २९
की धारा २ में
संशोधन।

“(२ क) “लाभार्थी” का तात्पर्य, इस अधिनियम और न्यास के गठन के अनुसार बनाये गये न्यास के विलेख या योजना में स्पष्ट किये गये न्यास के किसी उद्देश के अनुसार किसी भी लाभ के लिये हकदार किसी व्यक्ति से है और कोई अन्य व्यक्ति से नहीं है ;”।

(ख) खण्ड (४) के स्थान में, निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :-

“(४) “न्यायालय” का तात्पर्य, बॉम्बे के उच्च न्यायालय, से है ;”।

३. मूल अधिनियम की धारा ५ की, उप-धारा (२ क) में, खण्ड (ग) के स्थान में, निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :-

सन् १९५० का २९
की धारा ५ में
संशोधन।

“ (ग) जो, इस निमित्त विधि द्वारा स्थापित किन्ही विश्वविद्यालय से या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य विश्वविद्यालय की विधि की उपाधि धारण करता है और पूर्त संगठन में ५ वर्षों से अनून वर्ष के लिये कार्य किया है और पूर्त आयुक्त द्वारा विहित किये गये नियमों के अनुसार, संचालित की जानेवाली विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा की ऐसी उपाधि प्राप्त करने के पश्चात्, वरिष्ठ लिपिक या स्टेनो-टाइपिस्ट के श्रेणी से अनिम्न पद पर उत्तीर्ण की है। ”।

सन् १९५० का २९
की धारा २२ में
संशोधन।

४. मूल अधिनियम की धारा २२ की,—

(क) उप-धारा (१) में, निम्न परंतुक, जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

“ परंतु, उप या सहायक पूर्त आयुक्त का, यह समाधान होने पर कि, अनुबद्ध अवधि के भीतर परिवर्तन का रिपोर्ट न करने के लिये पर्याप्त कारण हैं, रिपोर्टिंग न्यासी द्वारा लागत के भुगतान के अध्यक्षीन, जो लोक न्यास प्रशासन निधि में जमा कराया जायेगा, परिवर्तन का रिपोर्ट करने के लिये नब्बे दिनों की अवधि विस्तारित कर सकेगा। ”;

(ख) उप-धारा (२) में, निम्न परंतुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

“ परंतु, न्यासियों और प्रबंधकों के नाम और पतों में और न्यासी के पदों के उत्तराधिकार में परिवर्तन होने के मामले में, उप या सहायक पूर्त आयुक्त, पंद्रह कार्य के दिनों के भीतर परिवर्तन प्राथमिक रूप से स्वीकार्य करेगा और ऐसी सूचना के प्रकाशन के दिनांक से तीस दिनों के भीतर ऐसे परिवर्तन के लिये आक्षेप बुलाने के लिये, सूचना जारी करेगा :

परंतु आगे यह कि, यदि, तीस दिनों के उक्त अवधि के भीतर आक्षेप प्राप्त नहीं होते हैं, तब प्रथम परंतुक के अधीन अंतिम रूप से परिवर्तन स्वीकृत करने का आदेश अंतिम होगा और उसमें की प्रविष्टी, विहित रित्या में धारा १७ के अधीन रजिस्टर में रखी जायेगी :

परंतु, यह भी कि, यदि तीस दिनों की उक्त अवधि के भीतर आक्षेप प्राप्त होते हैं, तब उप या सहायक पूर्त आयुक्त, विहित रीति में ऐसी जाँच संचालित करेगा और निष्कर्षों का अभिलेख इस धारा की उप-धारा (३) के द्वारा यथा उपबंधित, आक्षेपों को दर्ज करने की दिनांक से तीन महीनों के भीतर रखेगा। ”;

(ग) उप-धारा (३) में, “ या आवेदन ” शब्द अपमर्जित किये जायेंगे ;

सन् १९५० का २९
की धारा ३५ में
संशोधन।

५. मूल अधिनियम की धारा ३५ की, उप-धारा (१) में, द्वितीय परंतुक के पश्चात्, निम्न परंतुक, जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

“ परंतु, यह भी कि, यदि, द्वितीय परंतुक के अधीन किन्ही अन्य रित्या में, रकम निवेशित करने के लिये अनुमति का मंजूरी आदेश प्राप्त करने के लिये, पूर्त आयुक्त को, कोई लोक न्यास आवेदन करता है, तब, पूर्त आयुक्त, ऐसे आवेदन की प्राप्ति के दिनांक से तीन महीनों के भीतर ऐसा आवेदन विनिश्चित करेगा और जहाँ ऐसा करना व्यवहार्य नहीं हैं, वहाँ पूर्त आयुक्त उसी के लिये कारणों को अभिलिखित करेगा। ”।

सन् १९५० का २९
की धारा ३६ में
संशोधन।

६. मूल अधिनियम की धारा ३६ की,—

(क) उप-धारा (१) में, खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्न परंतुक, जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

“ परंतु, पूर्त आयुक्त, अंतरण, जिसके लिये खण्ड (क), (ख) या (ग) के अधीन पूर्व मंजूरी दी गई हैं, के पूर्ण होने के पूर्व, वह जैसा उचित समझे, उसके अधीन अधिकथित शर्तों को उपांतरित कर सकेगा :

परंतु आगे यह, कि, यदि, ऐसी शर्त किसी संविदा या वहन के कार्यान्वयन के लिये समय सीमा की हैं, तब, ऐसी शर्त के उपांतरण के लिये आवेदन, ऐसे अनुबद्ध समय के अवसान के पूर्व किया जायेगा। ”;

(ख) उप-धारा (१) के पश्चात्, निम्न उप-धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :-

“ (१ क) पूर्त आयुक्त, इस अधिनियम के अधीन तीस वर्षों से अधिक अवधि के लिये कोई पट्टा मंजूर नहीं करेगा। ”;

(ग) उप-धारा (२) में, निम्न परंतुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

“ परंतु, कोई भी मंजूरी, ऐसी मंजूरी प्रदान करने से पूर्व, पूर्त आयुक्त पर, छल द्वारा, ऐसी मंजूरी प्राप्त की गई हैं, के आधार के अलावा, वहन के कार्यान्वयन के पश्चात्, इस धारा के अधीन रद्द नहीं की जायेगी। ”;

(घ) उप-धारा (४) के अधीन, निम्न उप-धारा, जोड़ी जायेगी, अर्थात् :-

“ (५) उप-धारा (१) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, अपवादात्मक और असाधारण परिस्थितियों में, जहाँ पूर्व मंजूरी नहीं दी गई है, वह उप-धारा (१) के अधीन, अपेक्षित हैं, जिसके परिणामस्वरूप, न्यास अनेक व्यक्तियों का निकाय या वास्तविक क्रयकर्ता विपत्ति में आये, तब पूर्त आयुक्त, या निम्न परिस्थितियों में न्यासीयों द्वारा पूर्व-प्रभाव से न्यास की संपत्ति का अंतरण मंजूर कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि, —

(क) जहाँ आपाति परिस्थिति थी, जो ऐसा अंतरण उचित सिद्ध करें,

(ख) उक्त अंतरण के लिये बाध्य करने की आवश्यकता थी,

(ग) न्यास के हित में ऐसा अंतरण आवश्यक था,

(घ) संपत्ति प्रतिफल के लिये अंतरित की गई थी जो, विशेषज्ञों द्वारा प्रमाणित करने के लिये इस प्रकार अंतरित संपत्ति के प्रचलित बाजारमूल्य से, कम नहीं थी।

(ङ) बेहतर कीमत प्राप्त करने के लिये न्यासीयों की ओर से युक्तियुक्त प्रयास किये गये हैं,

(च) संपूर्ण अंतरण के भाग के दौरान, न्यासीयों का कार्य **वास्तविक** था और उक्त अंतरण से उन्होंने कोई भी लाभ, चाहे धनसंबंधी या अन्यथा हो, प्राप्त नहीं किया है, और

(छ) अंतरण रजिस्ट्रीकृत लिखत के कार्यान्वयन द्वारा प्रभावित हुआ था, यदि, तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन, दस्तावेज रजिस्टर करना आवश्यक हो। ”।

७. मूल अधिनियम की धारा ३६ क, की, उप-धारा (३) के पश्चात्, निम्न उप-धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :-

सन् १९५० का २९ की धारा ३६ में संशोधन।

“ (३ क) उप-धारा (३) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, अपवादात्मक और असाधारण परिस्थितियों में, जहाँ उप-धारा (३) के अधीन मंजूर देना अपेक्षित हैं, जिसके फलस्वरूप, न्यास, लाभधारी या **वास्तविक** अन्य पक्ष, विपत्ति में आते हो, तब पूर्त आयुक्त, पूर्व-प्रभाव से, न्यासीयों द्वारा, राष्ट्रीयकृत बैंक या अनुसूचित बैंक से रकम उधार लेने की मंजूरी दे सकेगा। ”।

८. मूल अधिनियम की धारा ४१ की, उप-धारा (२) में, “ धारा ७२ के उपबंधों के अध्याधीन, आदेश ” शब्दों और अंको के स्थान में, “ आदेश ” शब्द रखा जायेगा।

सन् १९५० का २९ की धारा ४१ में संशोधन।

९. मूल अधिनियम की धारा ४१ क की, उप-धारा (१) में, निम्न परंतुक, जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

सन् १९५० का २९ की धारा ४१ क में संशोधन।

“ परंतु, यदि, उप-धारा (१) के अधीन निदेश प्राप्त करने के लिए किसी न्यास के किसी न्यासी द्वारा कोई आवेदन किया गया है, तब पूर्त आयुक्त, उसकी प्राप्ति के दिनांक से तीन महीनों के भीतर ऐसा आवेदन निश्चित करेगा और यदि, ऐसा करना व्यवहार्य नहीं है, तब, पूर्त आयुक्त, उसी के लिये, कारणों को अभिलिखित करेगा। ”।

सन् १९५० का २९
की धारा ४१ घ में
संशोधन ।

१०. मूल अधिनियम की धारा ४१घ की,—

(क) उप-धारा (२) के स्थान में, निम्न उप-धारा, रखी जायेगी, अर्थात् :—

“ (२) (क) जब पूर्त आयुक्त, उप-धारा (१) के अधीन कार्यवाही करना प्रस्तावित करता हैं, तब, पूर्त आयुक्त, न्यासी या व्यक्ति, जिनके विरुद्ध, तब ही जब वह प्रथमदृष्ट्या उक्त व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये साधन प्राप्त होते हैं, कार्यवाही करना प्रस्तावित है की, सूचना जारी कर सकेगा।

(ख) न्यासी या व्यक्ति, जिसे खण्ड (क) के अधीन सूचना जारी की गई है, सूचना की प्राप्ति के दिनांक से पंद्रह दिनों के भीतर उसका जबाब प्रस्तुत करेगा।

(ग) यदि, व्यक्ति, खण्ड (क) के अधीन जारी सूचना का जबाब देने में विफल होता है या पूर्त आयुक्त के ध्यान में आता हैं कि, जवाब समाधान योग्य नहीं हैं, तब, पूर्त आयुक्त, जवाब देने या, यथास्थिति, जवाब देने में चूक के पंद्रह दिनों के भीतर उक्त व्यक्ति के विरुद्ध प्रभार विरचित करेगा, और ऐसे प्रभार चूकाने का अवसर उक्त व्यक्ति को देगा और उसके विरुद्ध प्रस्तुत किये गये सबूतों को ध्यान में लेने के पश्चात् और उसके पक्ष में, प्रभार विरचित करने के दिनांक से तीन महीनों के भीतर अधिहरण, हटाना या रद्द करने का आदेश मंजूर करेगा। यदि पूर्त आयुक्त को सूचना जारी करना, प्रभार विरचित करना और अंतिम आदेश, अनुबद्ध समय में मंजूर करना व्यवहार्य नहीं होता हैं, तब, वह उसी के लिये कारणों को अभिलिखित कर सकेगा।

(घ) अधिहरण, हटाने या रद्दकरण का आदेश, में, न्यासी के विरुद्ध विरचित प्रभार, उसका स्पष्टीकरण, यदि कोई हो और प्रत्येक प्रभार पर उपलब्धि, उसके कारणों के साथ, निश्चित करेगा। ”;

(ख) उप-धारा (५), अपमार्जित की जायेगी;

(ग) उप-धारा (६) के स्थान में, निम्न उप-धारा, रखी जायेगी, अर्थात् :—

“ (६) उप-धारा (१) के अधीन बनाये गये आदेश के विरुद्ध न्यायालय में अपील की जायेगी, यदि, जैसे कि, ऐसा निर्णय, जिला न्यायालय के निर्णय, मूल अधिकारिता के न्यायालय जिसमें अपील की गई हैं, के रूप में, आदेश के दिनांक से साठ दिनों के भीतर लिया गया हो। ”;

सन् १९५० का २९
की धारा ४१ ड में
संशोधन ।

११. मूल अधिनियम की धारा ४१ ड की, उप-धारा (४), (६) और (७), अपमार्जित की जायेगी।

सन् १९५० का २९
की धारा ४७ में
संशोधन ।

१२. मूल अधिनियम की धारा ४७ की, उप-धारा (५) के स्थान में, निम्न उप-धारा रखी जायेगी, अर्थात् :—

“ (५) उप-धारा (दो) के अधीन, पूर्त आयुक्त के आदेश के विरुद्ध न्यायालय में अपील की जायेगी, यदि, जैसे कि, ऐसा निर्णय जिला न्यायालय के निर्णय, मूल अधिकारिता के न्यायालय, जिसमें अपील की गई है, के रूप में, आदेश के दिनांक से साठ दिनों के भीतर लिया जायेगा, जो अन्यथा अंतिम होगा। ”।

सन् १९५० का २९
की धारा ५० में
संशोधन ।

१३. मूल अधिनियम की धारा ५० में,—

(क) खण्ड (दो) के स्थान में, निम्न खण्ड, रखा जायेगा, अर्थात् :—

“ (दो) जहाँ, लोक न्यास से जुडी या जुडे जाने के लिये तथाकथित संपत्ति को पुनः प्राप्त करने या अनुसरण करने या उसकी कार्यवाही के लिये या न्यासी, पूर्व-न्यासी, संक्रमण-ग्राही या किसी अन्य व्यक्ति, किंतु लोक न्यास, अतिचारी, पट्टेधारी या संक्रमण-ग्राही को प्रतिकूल रूप से धारण करनेवाले व्यक्ति नहीं, से कार्यवाही के लिये ऐसी संपत्ति के लिये निदेश या निर्णय आवश्यक है;”;

(ख) खण्ड (चार) में, उप-खण्ड (ज), अपमार्जित किया जायेगा :

(ग) तृतीय परंतुक के पश्चात्, निम्न स्पष्टीकरण, जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

“ स्पष्टीकरण.—इस धारा में, “ न्यायालय ” का तात्पर्य, बृहत् मुंबई में, शहर सिविल न्यायालय और अन्य जगह पर, जिला न्यायालय, से हैं। ”।

१४. मूल अधिनियम की धारा ५०क, की,—

सन् १९५० का २९
की धारा ५० क में
संशोधन ।

(क) उप-धारा (१), (२) और (३) में, पार्श्व टिप्पणी समेत “ पूर्त आयुक्त ” शब्द जहाँ कहीं वे आये हों, के स्थान में, “ सहायक या उप-पूर्त आयुक्त ” शब्द रखे जायेंगे।

(ख) उप-धारा (४) के स्थान में, निम्न उप-धारा, रखी जायेगी, अर्थात् :—

“ (४) उप-धारा (१) या उप-धारा (२) के अधीन विरचित और उप-धारा (३) के अधीन उपांतरित योजना, धारा ७० के अधीन पूर्त आयुक्त के निर्णय के अधीन, धारा ५० के अधीन न्यायालय के निर्णय के अधीन समाप्त या, यथास्थिति, बदली गयी योजना के रूप में, प्रभावी होगी। ”।

१५. मूल अधिनियम की धारा ५१ की,—

सन् १९५० का २९
की धारा ५१ में
संशोधन ।

(क) उप-धारा (२) के स्थान में, निम्न उप-धारा, रखी जायेगी अर्थात् :—

“ (२) यदि, पूर्त आयुक्त, उप-धारा (१) के अधीन वाद के संस्थापन के लिये सहमति देने से इन्कार करता है, तब, ऐसी सहमति के लिये आवेदन करने वाले व्यक्ति, न्यायालय में अपील कर सकेगा, जैसा कि यदि, ऐसा आदेश जिला न्यायालय द्वारा, जिससे, उक्त आदेश के दिनांक से साठ दिनों के भीतर अपील रखी गयी है, पारित निर्णय है, जो अन्यथा अंतिम होगी । ”;

(ख) उप-धारा (४) अपमार्जित की जायेगी।

१६. मूल अधिनियम की धारा ५५ के स्थान में, निम्न धारा, रखी जायेगी अर्थात् :—

सन् १९५० का २९
की धारा ५५ की
प्रतिस्थापना ।

“ ५५ (१) यदि, उसे या अन्यथा किये गये किसी आवेदन पर, सहायक या उप-पूर्त आयुक्त की तत्सदृश।
यह राय है कि,—

(क) मूल उद्देश जिसके लिए लोक न्यास सृजित था वह असफल हुआ है ;

(ख) किसी लोक न्यास की आय या किसी अतिरिक्त शेष राशि की उपयोग नहीं की गई है या उपयोग किये जाने की संभावना नहीं है;

(ग) किसी धार्मिक प्रयोजनों के लिए न्यास से अन्य लोक न्यास के मामले में, जिसके लिए लोक न्यास सृजित या लोक न्यासकर्ता का पूर्ण या भागतः मूल आशय या उद्देश्य कार्यान्वित करने के लिए लोक हित में इष्टकर, व्यवहार्य, वांछनिय, आवश्यक या उचित नहीं या और सम्पत्ति या लोक न्यास; या उसके किसी भाग की आय, किसी अन्य पूर्त या धार्मिक उद्देश के लिए लागू होगी ; या

(घ) धारा १० से १३ में उल्लिखित किन्ही मामलों में या धारा ५४ के अधीन न्यास में रखी हुई धर्मदाय राशि के विनियोग के लिए पूर्त आयुक्त के निर्देश आवश्यक है तब, सहायक या उप-पूर्त आयुक्त जाँच करने के पश्चात्, समुचित आदेशों को पारित करेगा और पूर्त आयुक्त को रिपोर्ट करेगा।

(२) पूर्त आयुक्त, स्वप्रेरणा से या सहायक या उप-पूर्त आयुक्त की रिपोर्ट पर निर्देश दे सकेगा और ऐसे निर्देश देने में वह लोक न्यासकर्ता के मूल आशय या उद्देश, जिसके लिए न्यास सृजित था, प्रभावी होगा।

(३) पूर्त-आयुक्त, किसी अन्य पूर्त या धार्मिक उद्देश्यों के तत्सदृश लागू किये जाने के लिए लोक न्यास या उसके किसी भाग की सम्पत्ति या आय का निदेश दे सकेगा। ऐसा करने में लोक न्यास के संबंध में पहले से ही पारित किसी डिक्री या आदेश के निबन्धनों या लोक न्यास के लिखत में अन्तर्विष्ट शर्तों को पहले से ही स्थायी या पहले से ही परिवर्तित किसी योजना बदलने के लिए पूर्त आयुक्त को विधिपूर्ण होगा।

(४) उच्च न्यायालय को इस धारा की उप-धारा (२) या, यथास्थिति, उप-धारा (३) के अधीन पूर्त आयुक्त द्वारा पारित निर्णय या आदेश के विरुद्ध कोई अपील की जायेगी, जैसा की यदि, ऐसा आदेश जिला न्यायालय द्वारा, जिससे उक्त आदेश के दिनांक से साठ दिनों के अधीन अपील रखी गई है, पारित निर्णय है, जो अन्यथा अंतिम होगा।”।

- सन् १९५० का २९
की धारा ५६ का
अपमार्जन ।
१७. मूल अधिनियम की धारा ५६, अपमार्जित की जायेगी।
- सन् १९५० का २९
की धारा ५६क का
अपमार्जन ।
१८. मूल अधिनियम की धारा ५६ क, अपमार्जित की जायेगी।
- सन् १९५० का २९
की धारा ६८ में
संशोधन ।
१९. मूल अधिनियम की धारा ६८ के खण्ड (ड) के पश्चात्, निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा,
अर्थात् :—
(ड-१) उन्हें मुकदमेबाजी से मुक्त करने के लिए लोक न्यास के बेहतर प्रशासन प्रोत्साहित करने और सुकर बनाने ;
(ड-२) न्यासी का स्वीकृत रजिस्ट्रीकरण जो न्यास को प्रस्तुत है और अन्य न्यासीयों द्वारा प्रतिवेदित नहीं है और धारा २२ के अधीन इसे रिपोर्ट के रूप में देखें और उसकी आवश्यक जाँच करने के पश्चात्, उसी के समान विनिश्चित करें;”
- सन् १९५० का २९
की धारा ६९ में
संशोधन ।
२०. मूल अधिनियम की धारा ६९ के,—
(क) खण्ड (ख) के स्थान में निम्न खण्ड रखा जायेगा, अर्थात् :—
“ (ख) धारा २०, २२ और २८ के अधीन उप या सहायक पूर्त आयुक्त के तथ्यों से अपीलों पर विचार करना और निपटना और धारा ५० क और ७९ के अधीन आदेश देने की शक्ति ;”;
(ख) खण्ड (ड) अपमार्जित किया जायेगा ;
(ग) खण्ड (ढ) के स्थान में, निम्न खण्ड, रखा जायेगा, अर्थात् :—
“ (ढ) न्यास राशि के तत्सदृश प्रयुक्त के लिए न्यासीयों को सूचना देने की शक्ति और उसी के समान समुचित आदेश पारित करने ;”;
- सन् १९५० का २९
की धारा ७० में
संशोधन ।
२१. मूल अधिनियम की धारा ७० की, उप-धारा (१) के,—
(क) खण्ड (ग-१) के पश्चात्, निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—
“ (ग-२) धारा ५०क के अधीन आदेश ;”;
(ख) खण्ड (घ) के पश्चात्, निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—
“ (घ-१) धारा ७९ की उप-धारा (१) के अधीन कोई आदेश ;”।
- सन् १९५० का २९
की धारा ७०क में
संशोधन ।
२२. मूल अधिनियम की धारा ७०क की, उप-धारा (२) के, खंड (ख) के स्थान में, निम्न खण्ड रखा जायेगा, अर्थात्,—
“ (ख) धारा ७० के अधीन बनाए अपील में, जिसमें आदेश पारित किया गया था ”।
- सन् १९५० का २९
की धारा ७१ का
अपमार्जन ।
२३. मूल अधिनियम की धारा ७१, अपमार्जित की जायेगी।
- सन् १९५० का २९
की धारा ७२ का
अपमार्जन ।
२४. मूल अधिनियम की धारा ७२, अपमार्जित की जायेगी।
- सन् १९५० का २९
की धारा ७३ में
संशोधन ।
२५. मूल अधिनियम की धारा ७३ में, निम्न परंतुक, जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—
“ परंतु, इस अधिनियम की धारा २२ के अधीन जाँच करते समय, उप या सहायक पूर्त आयुक्त, अभिसाक्षी की केवल प्रतिपरीक्षा के अध्यक्षीन शपथपत्रों के प्ररूप में साक्ष्य को अभिलिखित करेगा, यदि उसके द्वारा समुचित मामले में अनुमति दी गई है।”।

२६. मूल अधिनियम की धारा ७४क के स्थान में, निम्न धारा, रखी जायेगी, अर्थात् :—

सन् १९५० का २९
की धारा ७४क
का प्रतिस्थापन।

सन १९७४
का २।

“ ७४ क. जब राज्य सरकार इस प्रकार के निदेश, पूर्त आयुक्त, संयुक्त पूर्त आयुक्त या लेखा निदेशक या किसी उप या सहायक पूर्त आयुक्त को देता है तो, वह दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ की धारा ३४५ से ३४६ के अर्थान्तर्गत सिविल न्यायालय के समझे जायेंगे।”।

दंड प्रक्रिया संहिता,
१९७३ की धारा
३४५, और ३४६
के अर्थान्तर्गत पूर्त
आयुक्त, संयुक्त
पूर्ण आयुक्त, उप
सहायक पूर्त
आयुक्त आदि को
सिविल न्यायालय
समझा जायेगा।

२७. मूल अधिनियम की धारा ७७ के स्थान में, निम्न, रखा जायेगा, अर्थात् :—

सन् १९५० का २९
की धारा ७७ की
प्रतिस्थापना।

“ ७७. इस अधिनियम या नियमों के उपबंधों के अधीन दैय सभी रकमें, यदि अदा नहीं की गई है तो, किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भू-राजस्व के बकायें के रूप में वसूलिय होंगी।”।

अधिनियम और
नियमों के अधीन
रकमों की वसूली।

२८. मूल अधिनियम की धारा ७९ के स्थान में, निम्न धारा, रखी जायेगी अर्थात् :—

सन् १९५० का २९
की धारा ७९ का

“ ७९. (१) कोई प्रश्न, चाहे न्यास अस्तित्व में हो या न हो और ऐसा न्यास लोक न्यास हो या विशिष्ट संपत्ति ऐसे न्यास की संपत्ति है तो, उसका विचार इस अधिनियम द्वारा यथा उपबंधित उप या सहायक पूर्त आयुक्त द्वारा किया जायेगा।

प्रतिस्थापन।

(२) धारा ७० के अधीन पूर्त आयुक्त को सहायक या उप पूर्त आयुक्त के ऐसे निर्णय के विरुद्ध कोई अपील स्वीकार्य नहीं होगी।”।

२९. मूल अधिनियम की धारा ७९गग की, उप-धारा (३) के स्थान में, निम्न उप-धारा, रखी जायेगी, अर्थात् :—

सन् १९५० का २९
की धारा ७९गग में
संशोधन।

“ कोई अपील, उप या सहायक पूर्त आयुक्त द्वारा उप-धारा (२) के अधीन यदि प्रतिभूति प्रदान करने के आदेश के विरुद्ध पूर्त आयुक्त को किया गया होगा तो, उसपर उसका निर्णय अंतिम होगा और ऐसे अपील को धारा ७० के उपबंध लागू होंगे।”।

३०. मूल अधिनियम की धारा ८२ के स्थान में, निम्न धारा, रखी जायेगी, अर्थात् :—

सन् १९५० का
२९ की धारा ८२
की प्रतिस्थापना।

“ ८२. महानगरीय मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की श्रेणी से निम्न कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराधों का परीक्षण नहीं करेगा।”।

इस अधिनियम के
अधीन अपराधों
का निवारण।

३१. मूल अधिनियम की धारा ८४ की, उप-धारा (२) में,—

सन् १९५० का २९
की धारा ८४ में
संशोधन।

(क) खंड (ण) अपमार्जित किया जायेगा।

(ख) खंड (प) अपमार्जित किया जायेगा।

सन् १९५० का २९
की अनुसूची ख में
संशोधन।

३२. मूल अधिनियम की संलग्न अनुसूची ख में,—

(क) धारा ५०क से संबंधित प्रविष्टि में, स्तंभ (२) में—

“पूत आयुक्त” शब्दों के स्थान में, “सहायक या उप पूत आयुक्त” शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) धारा ५१(१) से संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्न प्रविष्टि, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

“५१. (२) पूत आयुक्त के निर्णय के विरुद्ध न्यायालय को अपील . . . १०० रुपयों”;

(ग) धारा ५५ से संबंधित प्रविष्टि में, स्तंभ (२) में “न्यायालय” शब्दों के स्थान में, “सहायक या उप-पूत आयुक्त” शब्द रखे जायेंगे ;

(घ) धारा ५६क से संबंधित प्रविष्टि, अपमार्जित की जायेगी ;

(ङ) धारा ७०(१) से संबंधित प्रविष्टि के, स्तंभ (२) में, “या धारा ५४ की उप-धारा (३) के अधीन आदेश” शब्दों, कोष्टकों और अंकों के स्थान में, “या धारा ५०क, धारा ५४ की उप-धारा (३) और धारा ७९ की उप-धारा (१) के अधीन, आदेश” शब्द, अंक, अक्षर और कोष्टक रखे जायेंगे;

(च) धारा ७१(१) से संबंधित प्रविष्टि, अपमार्जित की जायेगी ;

(छ) धारा ७२(१) से संबंधित प्रविष्टि, अपमार्जित की जायेगी ;

(ज) धारा ७२(४) से संबंधित प्रविष्टि, अपमार्जित की जायेगी ।

संदेहों का
निराकरण।

३३. संदेहों के निराकरण के लिए एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि, महाराष्ट्र लोक न्यास (द्वितीय सन् २०१७ संशोधन) अधिनियम, २०१७ (जिसे इसमें आगे “सन् २०१७ का उक्त संशोधन अधिनियम” कहा गया है), द्वारा का महा. यथा संशोधित महाराष्ट्र लोक न्यास अधिनियम में न होकर भी, उक्त संशोधन अधिनियम, २०१७ के प्रारंभण की दिनांक को किन्ही सिविल न्यायालय के समक्ष लंबित आवेदनों और अपीलों को प्रभावी करेगी; और ऐसे आवेदन या अपील सन् २०१७ के उक्त संशोधन अधिनियम के प्रारंभण की दिनांक के पूर्व बने रहे विधि के अनुसरण में ऐसे न्यायालय द्वारा सुलझाये जायेंगे या निपटाये जायेंगे।

(यथार्थ अनुवाद),

हर्षवर्धन जाधव,

भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. LVI OF 2017.

THE MAHARASHTRA LEGISLATURE MEMBERS (REMOVAL OF DISQUALIFICATION) (AMENDMENT) ACT, 2017.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक ६ सितम्बर, २०१७ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

नि. ज. जमादार,
प्रधान सचिव एवं विधि परामर्शी,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. LVI OF 2017.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA LEGISLATURE MEMBERS (REMOVAL OF DISQUALIFICATION) ACT.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५६, सन् २०१७।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, “महाराष्ट्र राजपत्र” में दिनांक ७ सितम्बर २०१७ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र विधानमंडल सदस्य (निरर्हता को हटाना) अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम।

सन् १९५६ **क्योंकि** इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र विधानमंडल सदस्य (निरर्हता को हटाना) अधिनियम का ५२। में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर हैं ; इसलिए, भारत गणराज्य के अड़सठवे वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता हैं, अर्थात् :-

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र विधानमंडल सदस्य (निरर्हता को हटाना) (संशोधन) अधिनियम, २०१७ कहलाए। संक्षिप्त नाम।

२. महाराष्ट्र विधानसभा या महाराष्ट्र विधानपरिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने या होने के लिये किसी व्यक्ति को निरर्हित किया जायेगा या निरर्हित नहीं किया गया समझा जायेगा, केवल इस तथ्य के कारण द्वारा कि, वह मुख्य सचेतक (चीफ व्हीप) या, यथास्थिति, सचेतक (व्हीप) का पद धारण करता है ; और, तदनुसार, महाराष्ट्र विधानमंडल सदस्य (निरर्हता हटाना) अधिनियम की अनुसूची एक की, प्रविष्टि २२ के पश्चात्, निम्न प्रविष्टि जोड़ी जायेगी, अर्थात् :-

राज्य विधानमंडल सदस्यता की निरर्हता की रोकथाम।

“ २३. महाराष्ट्र राज्य विधानमंडल में मुख्य सचेतक या सचेतक के पद।

स्पष्टीकरण.—(१) महाराष्ट्र विधानसभा के संबंध में “मुख्य सचेतक” या “सचेतक” अभिव्यक्ति का तात्पर्य, सदन का सदस्य जो तत्समय के लिये, उस सदन में मुख्य सचेतक (चीफ व्हीप) या सचेतक (व्हीप) के रूप में, सरकार बनानेवाले पक्ष द्वारा घोषित किया जाता हैं और अध्यक्ष द्वारा जैसा कि मान्यता दी जायेगी से हैं ; और सदन के वह सदस्य उसमें सम्मिलित है जो तत्समय के लिए, सदन के कुल सदस्यों में से कम से कम दस प्रतिशत सदस्य होनेवाले पक्ष द्वारा घोषित किया जाता है और अध्यक्ष द्वारा जैसा कि मान्यता दी जाती है ; और

(२) महाराष्ट्र विधानपरिषद के संबंध में “ मुख्य सचेतक ” या “ सचेतक ” अभिव्यक्ति का तात्पर्य, सदन का सदस्य, जो तत्समय के लिए, उस सदन में मुख्य सचेतक (चीफ व्हीप) या सचेतक (व्हीप) के रूप में सरकार बनाने वाले पक्ष द्वारा घोषित किया जाता है और सभापति द्वारा जैसा कि मान्यता दी जायेगी से है ; और उसमें सदन के वह सदस्य शामिल है जो तत्समय के लिए, सदन के कुल सदस्यों में से कम से कम दस प्रतिशत सदस्य होनेवाले पक्ष द्वारा जैसे कि घोषित किया जाता है और सभापती द्वारा मान्यता दी जाती है। ”।

(यथार्थ अनुवाद),

हर्षवर्धन जाधव,

भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. LVII OF 2017.

**THE MAHARASHTRA CO-OPERATIVE SOCIETIES (SECOND
AMENDMENT) ACT, 2017.**

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक ६ सितम्बर, २०१७ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

नि. ज. जमादार,
प्रधान सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. LVII OF 2017.

**AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA CO-OPERATIVE
SOCIETIES ACT, 1960.**

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५७, सन् २०१७।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, “महाराष्ट्र राजपत्र” में दिनांक ७ सितम्बर २०१० को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० में अधिकतर संशोधन संबंधी अधिनियम।

सन् १९६१ का महा. २४। **क्योंकि** इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :—

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र सहकारी संस्था (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१७ कहलाए।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भण।

(२) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करें।

१९६० का महा. २४। २. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (जिसे इसमें आगे, “मूल अधिनियम” कहा गया है) के अध्याय ग्यारह के पश्चात्, निम्न अध्याय, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

सन् १९६१ का महा. २४ में अध्याय ११-१क की निविष्टि।

“ अध्याय ग्यारह-१क

अकृषिक सहकारी साख संस्था

१४४-२क. (१) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, यह अध्याय अकृषिक सहकारी साख संस्था को लागू होगा।

अकृषिक सहकारी साख संस्था के अध्याय ग्यारह-१क की प्रयुक्ति।

(२) इस अध्याय के उपबंध, जिसे इसमें आगे यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त और अल्पीकरण करनेवाले नहीं होंगे।

परिभाषाएँ।

१४४-३क. इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो.—

(क) “अकृषिक सहकारी साख संस्था” का तात्पर्य, एक संस्था जिसका प्राथमिक उद्देश उसके सदस्यों को साख मुहैया करने तथा सदस्यों से निक्षेप राशियों स्वीकृत करने से है और इसमें,—

(एक) कोई नगर साख सहकारी संस्था ;

(दो) ग्रामीण अकृषिक साख सहकारी संस्था ;

(तीन) वेतन अर्जित करनेवालों की साख सहकारी संस्था ;

(चार) कोई अन्य संस्था या संस्थाओं के वर्ग जिसे राज्य सरकार, समय-समय पर **राजपत्र** में प्रकाशित सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें ;

(ख) “महाराष्ट्र राज्य अकृषिक सहकारी साख संस्था विनियामक बोर्ड” या “नियामक बोर्ड” का तात्पर्य, १४४-१३क के अधीन गठित बोर्ड, से है ;

(ग) “स्थिरीकरण और परिसमापन सहायक निधि” का तात्पर्य, धारा १४४-२५क के अधीन सृजित स्थिरीकरण और परिसमापन सहायक निधि, से है ;

कारोबार का प्ररूप जिसमें अकृषिक सहकारी साख संस्था शामिल हो सकेगी।

१४४-४क. महाराष्ट्र सहकारी संस्था (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१७ (जिसे इसमें आगे, इस अध्याय में, “उक्त संशोधन अधिनियम, २०१७” कहा गया है) के प्रारम्भण के दिनांक से अकृषिक सहकारी साख संस्था, कारोबार के किसी एक या अधिक निम्न प्ररूपों में शामिल हो सकेगी, अर्थात् :—

सन् २०१७ का महा ५७।

(क) सदस्यों से उधार-ग्रहण करना, संचयन करना या निक्षेपों को स्वीकृत करना, या तो सुरक्षा पर या बिना सुरक्षा की राशि, के अग्रिम ऋणों और अग्रिमों का प्रबंध करना, सदस्यों को स्वयं द्वारा सुरक्षित निक्षेप कक्ष मुहैया करना ;

(ख) किसी अपने दावे के समाधान या अंशतः समाधान में ऐसी अकृषिक सहकारी साख संस्था के कब्जे में आ सकनेवाली किसी सम्पत्ति का प्रबन्ध करने, विक्रय करने और वसूली करने ;

(ग) किसी सम्पत्ति का अर्जन और धारण करने और सामान्यतः व्यवहार करने या किसी ऐसी सम्पत्ति में किसी अधिकार, हक या हित जो किसी कर्ज या अग्रिम के लिये सुरक्षा का प्रकार या सुरक्षा का भाग हो सकेगा या किसी ऐसी सुरक्षा से सम्बन्धित हो सकेगा ;

(घ) अकृषिक सहकारी साख संस्था के प्रयोजन के लिये आवश्यक या सुविधाजनक किसी भवन या कार्य के अधिग्रहण, संनिर्माण, रखरखाव और परिवर्तन करने ;

(ङ) अकृषिक सहकारी साख संस्था की सम्पत्ति और अधिकारों के सभी या किसी भाग का विक्रय करने, सुधार करने, प्रबन्ध करने, विकास करने, विनिमय करने, पट्टे पर देने, बंधक बनाने, निपटान करने या लेखे में मोड़ देने या अन्यथा व्यवहार करने ;

(च) इस धारा में यथा विनिर्दिष्ट स्वरूप का ऐसा कारोबार है तब अकृषिक सहकारी साख संस्था के किसी सदस्य के कारोबार के संपूर्ण या किसी भाग का ऐसे सदस्य से ऋण अग्रिम की वसूली के, प्रयोजन के लिए अर्जन करने और उसे हाथ में लेने ;

(छ) अकृषिक सहकारी साख संस्था के कारोबार के संवर्धन या उन्नति के लिए आनुषंगिक या सहायक सभी ऐसी अन्य बातें करना ;

(ज) तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसरण में, रजिस्ट्रार की पूर्व मंजूरी से अस्तियों के संनिर्माण के लिए स्वयं या चाहनेवाले सहायता कृत्यों को हाथ में लेना ;

(झ) कारोबार का कोई अन्य प्ररूप जो राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, कारोबार में लगे हुए प्ररूप में विनिर्दिष्ट करें जो अकृषिक सहकारी साख संस्था के लिए विधिपूर्ण होगा।

(२) उप-धारा (१) के अधीन निर्दिष्ट है कारोबार से अन्य कारोबार के प्ररूप के मामले में कारोबार अनुज्ञाप्राप्त नहीं होकर के किसी अन्य प्ररूप के मामले में उक्त संशोधन अधिनियम, २०१७ के प्रारम्भण के दिनांक से पूर्व किसी अकृषिक सहकारी साख संस्था द्वारा पहले ही हाथ में लिया गया है तो, ऐसी संस्था, उक्त संशोधन अधिनियम, २०१७ के प्रारम्भण की दिनांक से अठारह महीनों के भीतर ऐसे कारोबार को समाप्त करेगी :

परन्तु, यह कि, विशेष मामलों में, यदि रजिस्ट्रार का यह समाधान होता है कि, अकृषिक सहकारी साख संस्था का कोई विस्तार उनके हित में हैं तो वह, बारह महीने के अनधिक अवधि जो इस प्रकार का अवधि कुल मिलाकर तीस महीनों से अनधिक हो तथा शर्तों तथा निबंधनों के अध्वधीन, जैसा वह उचित समझे ऐसे अवधि तक वह अवधि विस्तारित कर सकेगी।

१४४-५क. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट अन्य किसी बात के होते हुए भी, अकृषिक सहकारी साख संस्था, किसी व्यक्ति से, जो उसका सदस्य नहीं है, से निक्षेप स्वीकृत नहीं करेगा। यदि कोई संस्था, जिसने उक्त संशोधन अधिनियम, २०१७ के प्रारम्भण के दिनांक से पूर्व गैर-सदस्यों से निक्षेप स्वीकृत किया है, तो वह संस्था या तो उक्त संशोधन अधिनियम, २०१७ के प्रारम्भण से दो वर्षों के भीतर सभी गैर सदस्यों की सदस्य के रूप में नामांकन करेगा या उनके निक्षेप का प्रतिदाय करेगा।

गैर सदस्यों से निक्षेप की स्वीकृति का प्रतिषेध।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “सदस्य” नाममात्र सदस्य सम्मिलित नहीं हैं।

१४४-६क. धारा १४४-४क या किसी संविदा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अकृषिक सहकारी साख संस्था, उसे दी गयी या उसके द्वारा रखी गई सुरक्षा के वसूली के संबंध में या किसी व्यापार में लगी हुई, या अन्यो के लिए मालों के क्रय, विक्रय या वस्तु-विनिमय को छोड़कर मालों का क्रय करने, विक्रय करने या वस्तु-विनिमय करने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यवहार करेगी।

व्यापार का प्रतिषेध।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “मालों” का तात्पर्य, स्थावर संपत्ति के प्रत्येक किस्म अभियोज्य दावों, स्टॉक, धन, सोना-चांदी और सिक्कों से अन्य और धारा १४४-४क, की उप-धारा (१) में निर्दिष्ट सभी लिखितों से है।

१४४-७क. धारा १४४-४क में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी अकृषिक सहकारी साख संस्था, किसी तरह अर्जित किसी स्थावर संपत्ति को धारण कर सकेगी, उसे अपने उपयोग के लिए, उसी के सिवाय, उसके अर्जन से या उक्त संशोधन अधिनियम, २०१७ के प्रारम्भण से सात वर्षों से अधिक किसी अवधि के लिए, जो भी बाद का हो या इस धारा के अधीन ऐसी अवधि के किसी विस्तार या ऐसी संपत्ति का निपटान ऐसी अवधि या, यथास्थिति, विस्तार अवधि के भीतर किया जायेगा :

अकृषिक सहकारी साख संस्था के लिए संपत्ति का निपटान आवश्यक नहीं है।

परन्तु, अकृषिक सहकारी साख संस्था यथा उपरोक्त सात वर्षों की अवधि के भीतर, उसके निपटान को सुकर बनाने के प्रयोजन के लिए किसी ऐसी संपत्ति का व्यवहार करेगी :

परन्तु यह और कि, रजिस्ट्रार किसी विशिष्ट मामले में, तीन वर्षों से अनधिक ऐसी अवधि द्वारा उपरोक्त सात वर्ष की अवधि बढ़ा सकेगी जहाँ उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विस्तार अकृषिक सहकारी साख संस्था के हितों में होगा और शर्तों तथा निबंधनों के अध्वधीन जैसा, वह उचित समझे ऐसे भी होगा।

१४४-८क. अकृषिक सहकारी साख संस्था, विनियामक बोर्ड द्वारा राजपत्र में यथा अधिसूचित प्रशासकीय तथा आस्थापना व्ययों पर की सीमा से अधिक व्यय नहीं करेगी।

प्रशासकीय तथा आस्थापना व्ययों पर सीमा।।

१४४-९क. अकृषिक सहकारी साख संस्था, अपने पास आरक्षित नकद या बैंक के चालू खाते में औसत शेष या समतुल्य रकम के जरिए या अल्पकालिक निक्षेप ऐसे प्रतिशत समतुल्य राशि बैंको में पंद्रह दिनों से अधिक नहीं होगी जो उसके कुल निक्षेप से पाँच प्रतिशत से कम न हों, यथा विनियामक बोर्ड, समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे बनाये रखेगी और इस प्रकार धारण की गई रकम कुल और प्रत्येक ब्रांच में दर्शानेवाली विवरणी प्रत्येक तिमाही के अंतिम पंद्रह दिन को या पहले संबंधित रजिस्ट्रार, सहकारी संस्था को प्रस्तुत करेगी :

आरक्षित नकद के संपोषण के लिये संस्था।

परंतु, धारा १४४-१०क में विनिर्दिष्ट सीमा के अधिक्य में बनाए रखे गए कानूनी परिसमापन पर निकाले गए किसी ओवर ड्राफ्ट इस धारा के प्रयोजनों के लिए, आरक्षित के रूप में माना जाएगा।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिए “बैंक” पद का तात्पर्य, धारा ७० में यथा विवरणित बैंक से है।

कानूनी
परिनिर्धारित
आरक्षित निधि।

१४४-१०क. प्रत्येक अकृषिक सहकारी साख संस्था, अपने पास कानूनी परिनिर्धारित आरक्षित निधि या बैंक के मियादी निक्षेप में औसत शेष या समतुल्य रकम, यथा विनियामक बोर्ड समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे जो उसके कुल निक्षेप से बीस प्रतिशत से कम न हों या चालीस प्रतिशत से अनधिक ऐसे प्रतिशत के रूप में पोषित की जायेगी और इस प्रकार धारण की गई रकम दर्शानेवाली विवरणी प्रत्येक तिमाही के अंतिम पंद्रह दिन को या के पहले संबंधित रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेगी :

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिए “बैंक” पद का तात्पर्य, धारा ७० में यथा विवरणित बैंक से है।

कर्ज और अग्रिमों
पर निर्बन्धन।

१४४-११क. (१) अकृषिक सहकारी साख संस्था,—

(क) धारा ४४ के अनुसार अपने स्वयं के शेषों की प्रतिभूति पर किसी कर्ज या अग्रिम के लिये अनुमति नहीं देगी ;

(ख) किसी कर्ज या अग्रिम या के पक्ष में प्रदान करने के लिये किसी से वचनबद्ध नहीं होगी,—

(एक) यथा अपेक्षित अपने किसी विद्यमान निर्देशकों और उसके परिवार सदस्यों उसके अपने नियत निक्षेपों या इसी संस्था के परिवार सदस्य के नाम में धारित को छोड़कर जहाँ वह निदेशक है जहाँ उसके द्वारा पूरी सुरक्षा दी गई है ;

(दो) किसी फर्म या कम्पनी जिसमें किसी निदेशक और उसके परिवार सदस्य का सम्बद्ध है स्वामी, भागीदार, प्रबंधक, गारंटीकर्ता या मुख्य शेरर धारक या जिसमें वह वास्तविक सम्बद्ध धारण करता है।

(२) जहाँ कोई कर्ज या अग्रिम अकृषिक सहकारी साख संस्था द्वारा मंजूर या अनुदत्त किया गया है ऐसी प्रतिबद्धता के लिए उसे उप-धारा (१) के खण्ड (ख) द्वारा मंजूर संवितरित किया गया नहीं है कि प्रवृत्त दिनांक को जिस दिनांक को कर्ज या अग्रिम दिया गया है या उक्त संशोधन अधिनियम, २०१७ के प्रारम्भण के बाद अकृषिक सहकारी साख संस्था द्वारा मंजूर किया गया है, किन्तु ऐसे प्रारम्भण से पूर्व उसमें प्रविष्ट प्रतिबद्धता के अनुसरण में है तो, कर्ज या अग्रिम के कारण एकत्रित करके ब्याज समेत अकृषिक सहकारी साख संस्था को देय रक्कम की वसूली के लिए कदम उठाये जायेंगे, यदि, कोई हो, कर्ज या अग्रिम की मंजूरी के समय पर नियत अवधि के भीतर उस पर देय, या जहाँ उक्त संशोधन अधिनियम, २०१७ के प्रारम्भण के दिनांक से दो वर्ष की अवधि के अवसान से पूर्व, ऐसी कोई अवधि नियत नहीं की गई है।

(३) यदि कोई प्रश्न प्रोद्भूत होता है जहाँ इस धारा के प्रयोजन के लिए कर्ज या अग्रिम का कोई संव्यवहार होता है तो वह, रजिस्ट्रार को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका निर्णय उसपर अंतिम होगा।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिए “परिवार” पद का तात्पर्य, धारा ७५ की उप-धारा (२) में किये गये स्पष्टीकरण के समान अर्थातर्गत से है।

ऋण को छूट देने
की शक्ति पर
निर्बन्धन।

१४४-१२क. (१) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अकृषिक सहकारी साख संस्था, रजिस्ट्रार के पूर्वानुमोदन के सिवाय और विनियामक बोर्ड के परामर्श से, उसके द्वारा देय किसी ऋण के संपूर्ण या अंशतः छूट नहीं देगी,—

(क) उसके किसी विगत और वर्तमान निदेशकों और उनके परिवार के सदस्य ; या

(ख) कोई फर्म या कंपनी में, जिसमें उसका कोई विगत या वर्तमान निदेशक, निदेशक, भागीदार, प्रबंध एजेंट या गारण्टर या प्रमुख शेअरधारक या जिसमें वह कोई हित रखता है के रूप में उसके परिवार का सदस्य इच्छुक है।

(२) उप-धारा (१) के उपबंधों के उल्लंघन में दी गई कोई छूट शून्य और प्रभाहीन होगी।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए “ परिवार ” पद का तात्पर्य, धारा ७५ की उप-धारा (२) में किये गये स्पष्टीकरण एक के समान अर्थात्गत होगा।

१४४-१३क. राज्य सरकार, उक्त संशोधन अधिनियम, २०१७ के प्रारम्भण के पश्चात्, यथा संभव शीघ्र, महाराष्ट्र राज्य राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन या के द्वारा समनुदेशित ऐसे कर्तव्यों तथा कृत्यों का अकृषक सहकारी साख संस्था निर्वहन करने के लिए, महाराष्ट्र राज्य अकृषक सरकारी साख संस्था विनियामक बोर्ड गठित करेगी। विनियामक बोर्ड।

१४४-१४क. विनियामक बोर्ड, निम्न सदस्यों से गठित होगा, अर्थात् :—

विनियामक बोर्ड का गठन।

(क) रजिस्ट्रार, जो विनियामक बोर्ड का अध्यक्ष होगा ;

(ख) रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त, अतिरिक्त रजिस्ट्रार से अनिम्न श्रेणी का कोई अधिकारी ;

(ग) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जानेवाले किसी सहकारी बैंक से उप महा प्रबंधक से अनिम्न श्रेणी के दो सेवा निवृत्ती अधिकारी,—

(एक) जो, बैंक के उप महा प्रबंधक से अनिम्न श्रेणी के अधिकारी के रूप में कम-से-कम दस वर्ष का अनुभव रखनेवाले हो, तथा उनके विरुद्ध अनुशासनिक या कोई अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की गई हो ; तथा

(दो) जिसमें से एक ऐसे बैंक की सेवा जिसके परिचालन का क्षेत्र संपूर्ण राज्य है, से निवृत्त होगा तथा अन्य एक ऐसे बैंक की सेवा, जिसके परिचालन का क्षेत्र राज्य से कम है, से निवृत्त होगा ;

(घ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जानेवाला एक चार्टर्ड अकौंटेंट, जिसका नाम रजिस्ट्रार द्वारा रखे गए लेखा परीक्षक के पैनल पर दिखाई देता है, तथा अकृषक सहकारी साख संस्था के लेखापरीक्षण का कम से कम दस वर्ष का अनुभव होनेवाला हो ;

(ङ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जानेवाले अकृषक सहकारी साख संस्था के चार प्रतिनिधि, जो विगत तीन क्रमवर्ती वर्षों में, “ क ” संपरीक्षा वर्ग का दर्जा प्राप्त किए हैं,—

(एक) जिसे अकृषक सहकारी साख संस्था के निदेशक के रूप में कम से कम दस वर्ष का अनुभव हो तथा धारा ७३ गक में यथा विनिर्दिष्ट किसी संस्था के सदस्य होने के लिए या नियुक्त होने के लिए या सदस्य के रूप में नामनिर्देशित या सहयोजित या चयनित होने के लिए अयोग्य नहीं होगा ; तथा

(दो) उसमें से एक, ऐसी संस्था का निदेशक होगा जिसके परिचालन का क्षेत्र संपूर्ण राज्य है ; तथा और एक ऐसी संस्था का निदेशक होगा जिस संस्था का परिचालन का क्षेत्र एक जिले से कम नहीं है ; तथा और दो ऐसी संस्था के निदेशक होंगे जिस संस्था के परिचालक का क्षेत्र एक जिले से कम है।

१४४-१५क. रजिस्ट्रार द्वारा उप-रजिस्ट्रार से अनिम्न श्रेणी के किसी अधिकारी की विनियामक बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्ति की जायेगी। विनियामक बोर्ड के सचिव।

१४४-१६क. राज्य सरकार के प्रसादपर्यंत के अध्यक्षीन, विनियामक बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्य का पदावधि उसके नामनिर्देशन के दिनांक से तीन वर्ष का होगा। विनियामक बोर्ड का गैर-सरकारी सदस्य, केवल एक बार पुनःनामनिर्देशित हो सकेगा। विनियामक बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्यों की पदावधि।

गैर-सरकारी सदस्य का इस्तिफा। **१४४-१७क.** गैर-सरकारी सदस्य, किसी भी समय पर, स्वयं अपने स्वहस्ताक्षर से लिखित में, विनियामक बोर्ड के अध्यक्ष को सम्बोधित करके, अपना इस्तिफा दे सकेगा। विनियामक बोर्ड के सदस्य का इस्तिफा, उसके अध्यक्ष द्वारा प्राप्ति पर यथासंभव शीघ्र लागू होगा।

गैर-सरकारी सदस्यों का हटाना। **१४४-१८क.** राज्य सरकार, गैर-सरकारी सदस्य को उसके पद से हटा सकती है, यदि वह सदस्य,—

(क) दिवालिया है ; या

(ख) जो सरकार की राय में नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त होकर दोषसिद्ध ठहराया गया है और उसे कारावास से दंडित किया गया है ; या

(ग) विकृत चित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा उसे इस प्रकार घोषित ठहराया गया है ;

(घ) सदस्य के रूप में करने के लिए अस्वीकृत किया है या कार्य करने के लिए असमर्थ है ; या ;

(ङ) धारा ७३गक में यथा विनिर्दिष्ट किसी संस्था के समिति का सदस्य होने के लिए या नियुक्त होने के लिए या समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्देशित या सहयोजित या चयनित होने के लिए अयोग्य है।

आकस्मिक रिक्तियाँ कैसे भरी जानी चाहिए। **१४४-१९क.** विनियामक बोर्ड में की आकस्मिक रिक्तियाँ, धारा १४४-१४क में यथा उपबंधित रित्या में तथा जब वे रिक्त होने के रूप में भरी जायेगी।

विनियामक बोर्ड के कारोबार का संचालन। **१४४-२०क.** विनियामक बोर्ड के बैठक की सूचना, गणपूर्ति तथा विनियामक बोर्ड के कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया, जैसा की विहित किया जाए ऐसी होगी।

विनियामक बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्यों को अनुमति। **१४४-२१क.** विनियामक बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्यों को, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय से विनिर्दिष्ट करे ऐसे, स्थिरीकरण तथा परिसमापन सहायता निधि से ऐसा भत्ता अदा किया जायेगा।

विनियामक बोर्ड के कृत्य तथा शक्तियाँ। **१४४-२२क.** (१) इस अधिनियम तथा तद्धीन बनाने गये नियमों के उपबंधों के अधधीन, विनियामक बोर्ड को निम्न मामलों के लिये, विनियम विरचित करने की शक्ति होगी, अर्थात् :—

(क) किसी संस्था द्वारा किसी व्यक्तिगत सदस्य से संग्रहित की जा सके, ऐसी अधिकतम जमा रकम ;

(ख) जमाराशि और सुरक्षित तथा असुरक्षित ऋण के लिये ब्याज के अधिकतम तथा न्युनतम दरों ;

(ग) व्यक्तिगत सदस्य तथा सभी उससे संबंधित लेखों को मंजूर की जा सकनेवाले ऋण की अधिकतर सीमा ;

(घ) आरक्षित नकद के रूप में अकृषिक सहकारी साख संस्था द्वारा संपोषित की जानेवाली अधिकतम सीमा ;

(ङ) स्थिरीकरण तथा परिसमापन सहायता निधि के लिये अकृषिक सहकारी साख संस्था द्वारा किये जाने वाले अंशदान का दर तथा उसका आवर्तन जो वार्षिक या अन्यथा हो सकेगा ;

(च) स्थिरीकरण तथा परिसमापन सहायता निधि से जमा राशि के प्रतिदाय के लिये सहायता प्राप्ति के लिये पात्र होने के लिये संस्था के लिये मापदण्ड ;

(छ) अकृषिक सहकारी साख संस्था द्वारा, उसके प्रशासनिक तथा स्थापना व्ययों पर उपगत किये जाने के लिये अनुमतिप्राप्त परिव्यय की अधिकतम सीमा।

(२) विनियामक बोर्ड को निम्न मामलों के लिये मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करने की शक्ति होगी :—

(क) अपालन संपत्ति का वर्गीकरण ;

(ख) संस्था के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिये और अन्य अधिकारी तथा कर्मचारिवृंद की न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएँ और प्रशिक्षण ;

(ग) जो संस्था के लिये पात्रता मापदण्ड स्थिरीकरण और परिसमापन सहायता निधि के अंशदान कर सकेगी ;

(घ) आस्तियाँ पुनर्रचना कंपनी के रूप में या अन्यथा तत्समय किसी विधि के अनुसरण में कार्य करने के लिये एक या अधिक कंपनियों या संस्थाओं को मान्यता।

(ङ) उन मामलों पर सामान्य मार्गदर्शन सिद्धांत जिन्हे विनियामक बोर्ड उचित समझता है और अकृषिक सहकारी संस्था के हित में समय-समय से जारी करना आवश्यक हैं।

(३) राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, विनियामक बोर्ड पर, जैसा कि वह समय-समय से उचित समझे, ऐसे किन्हीं अन्य कृत्य तथा शक्तियाँ प्रदत्त कर सकेगी।

१४४-२३क. (१) अकृषिक सहकारी साख संस्था, धारा १४४-२२क के अनुसार विनियामक बोर्ड द्वारा जारी विनियमों तथा मार्गदर्शक सिद्धांतों का अनुसरण करने के लिये बाध्य होगी।

अकृषिक सहकारी साख संस्थाओं पर बाध्य होनेवाले विनियम तथा मार्गदर्शक सिद्धांत।

(२) रजिस्ट्रार, विनियामक बोर्ड द्वारा, समय-समय से विरचित विनियमों और जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसरण की रिपोर्ट, संस्था से माँग सकेगा।

१४४-२४क. (१) रजिस्ट्रार को, जमाकर्ताओं तथा, या सदस्यों के हितों के लिये हानिकारक रित्या या अकृषिक सहकारी साख संस्था के हित के लिये प्रतिकूल रित्या किन्हीं अकृषिक सहकारी साख संस्था के कार्यकलापों को रोकने के उद्देश से, किसी अकृषिक सहकारी साख संस्था के मामले में, सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, यदि वह ऐसा करने के लिये समाधानी हो जाता है तो, ऋणस्थगन अधिरोपित करने या निदेश जारी करने की शक्तियाँ होंगी।

अकृषिक सहकारी साख संस्था का ऋणस्थगन तथा निदेश।

(२) इस धारा के प्रयोजनों के लिये, रजिस्ट्रार,—

(क) निर्निर्दिष्ट किये जाये ऐसे दिनांक तक, जमाराशि का प्रतिदाय करने या उसे निकालने के लिये किन्हीं अकृषिक सहकारी साख संस्था पर निर्बंधन अधिरोपित करना ;

(ख) जब संस्था किन्हीं अधिक या अधिकतर जमाराशि का स्वीकार तब तक नहीं कर सकती जबतक वह, कानूनी परिसमापन अनुपात या नकद आरक्षित अनुपात से संबंधित कतिपय निबंधनों या किन्हीं अन्य निबंधनों का अनुसरण नहीं करती, है, आदेश जारी करना ; या

(ग) उप-धारा (१) के अधीन जारी किन्हीं ऋणस्थगन या निदेशों का उपांतरण करना या रद्द करना, और किन्हीं ऋणस्थगन या निदेश के ऐसे उपांतरण या रद्द करने के दौरान, जिसके अध्यक्षीन, उपांतरण या रद्दकरण प्रभावी होगा, जैसे कि वह उचित समझे, ऐसे निबंधनों को अधिरोपित कर सकेगा।

१४४-२५क. राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, “ स्थिरीकरण तथा परिसमापन सहायता निधि ” सृजित करेगा और अकृषिक सहकारी साख संस्था द्वारा किया गया अंशदान, सहायता की रकम का प्रतिकर और उसपर का ब्याज, उधार, प्राप्त परिदान तथा सरकार द्वारा प्राप्त कोई सहायता का समावेश होगा।

स्थिरीकरण तथा परिसमापन सहायता निधि का गठन।

१४४-२६क. (१) प्रत्येक अकृषिक सहकारी साख संस्था, विनियामक बोर्ड द्वारा **राजपत्र** में, समय-समय से, अधिसूचित किये जाये, ऐसे दर पर और ऐसे रित्या स्थिरीकरण तथा परिसमापन निधि में, वार्षिक या अन्यथा अंशदान करेगा।

संस्थाओं द्वारा निधि में किया गया अंशदान।

(२) एकबार किये गये अंशदान का कोई भी भाग का, किन्ही भी कारण के लिये किन्ही अकृषिक सहकारी साख संस्था को, प्रतिदायित किया जाएगा।

निधि का उपयोग।

१४४-२७क. (१) “स्थिरीकरण तथा परिसमापन सहायता निधि” विनियामक बोर्ड द्वारा, समय-समय से, अभिनिर्धारित ऐसी निबंधनों तथा शर्तों पर धारा १४४-१०क में यथा विनिर्दिष्ट कानूनी परिसमापन अनुपात के संपोषण के लिये, अर्ह अकृषिक सहकारी साख संस्था का परिसमापन सहायता मुहैया करने के लिये, उपयोग में लाया जायेगा।

(२) स्थिरीकरण तथा परिसमापन सहायता निधि, अकृषिक सहकारी साख संस्था के सदस्यों के निक्षेप, जिसे इस धारा की उप-धारा (३) के अधीन, यथा अधिसूचित निपटान के प्रारम्भण दिनांक के पश्चात्, परिसमापन में ली गई थी, के संदर्भ में वादों के निपटान के लिये उपयोग में लाया जायेगा। प्रति सदस्य जमाकर्ता निपटान की रकम, जमाकर्ता के निक्षेप की वास्तविक रकम या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर **राजपत्र** में जिसे अधिसूचित करेगा वह रकम होगी, जी भी कम हो।

(३) इस धारा की उप-धारा (२) के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार, **राजपत्र** में, निपटान के प्रारम्भण का दिनांक अधिसूचित करेगा।

निधि के प्रचालन तथा निवेशों का रखरखाव।

१४४-२८क. (१) स्थिरीकरण तथा परिसमापन सहायता निधि का रखरखाव तथा परिचालित विनियामक बोर्ड द्वारा होगा।

(२) स्थिरीकरण तथा परिसमापन निधि द्वारा सृजित राशि, विनियामक बोर्ड के नाम में, किसी राष्ट्रीयीकृत बैंक, या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक या विगत तीन वर्षों के दौरान “क” लेखा श्रेणी पाने वाले जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक या दो सौ करोड रुपये या अधिक रुपयों के मूल्य की किसी बैंक में खाता खोलकर रखी जाएगी।

(३) स्थिरीकरण तथा परिसमापन सहायता निधि में जमा राशि, उपरोल्लिखित किसी बैंकों में निवेशित की जा सकेगी। किसी भी बैंक में इस प्रकार निवेशित राशि, ऐसे निवेश के समय, उक्त समग्र निधि के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(४) इस धारा के प्रयोजनों के लिये, विनियामक बोर्ड की, निम्न शक्तियाँ, होगी :—

(क) पात्र संस्था को, आदेश में यथा विवरणित ऐसे ब्याज दर, पुर्भुगतान सूची पर, विनियामक बोर्ड द्वारा, यथाविहित कानूनी परिसमापन अनुपात के रखरखाव के लिये, स्थिरीकरण तथा परिसमापन निधि से रकम मंजूर करने, निकालने तथा भुगतान करने का आदेश पारित करना ;

(ख) अकृषिक सहकारी साख संस्था के सदस्यों के निक्षेप जिसे निपटान के प्रारम्भण के दिनांक के पश्चात् परिसमापन में लिया गया था, के भुगतान के लिये, स्थिरीकरण तथा परिसमापन सहायता निधि से रकम मंजूर करने और निकालने के लिये, आदेश पारित करना ;

(ग) परिमापक द्वारा निक्षेप के पुर्भुगतान के लिये, मदद या सहायता मुहैया करने के लिये यथा आवश्यक ऐसे विनियम विरचित करना। विनियामक बोर्ड, सरकार द्वारा, **राजपत्र** में समय-समय से अधिसूचित रकम के अध्यक्षीन, सहायता की मात्रा या, यथास्थिति, मदद की रकम विनिश्चित करने के लिये सक्षम होगा।

(५) विनियामक बोर्ड, संस्था से या, यथास्थिति, संस्था के परिसमापक से इसीप्रकार निकाली गई रकम की वसूली का मॉनिटर करेगा।

अंशदान परिसमापन सहायता या वित्तीय सहायता के बकायों की वसूली।

१४४-२९क. यदि, अ-कृषिक सहकारी साख संस्था, स्थिरीकरण तथा परिसमापन सहायता निधि में अंशदान करने में विफल होता है या संस्था, परिसमापन सहायता के लिये उपलब्ध रकम के पुर्भुगतान करने में विफल होता है या परिसमापक, उक्त निधि को, निक्षेपक के निपटान के लिये उपलब्ध वित्तीय सहायता के पुर्भुगतान में विफल होता है, तब रजिस्ट्रार, भू-राजस्व के बकाये के रूप में, अंशदान, परिसमापन सहायता या, यथास्थिति,

निपटान आदि की बकाये की रकम की वसूली करने के लिये, सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, वसूली प्रमाणपत्र जारी करेगा और इस प्रकार देय रकम और ब्याज को संस्था या, यथास्थिति, परिसमापक के सभी अन्य दायित्वों के संबंध में, प्राथमिकता में प्रथम श्रेणी होगी।

१४४-३०क. विनियामक बोर्ड का सचिव, विनियामक बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाये ऐसे प्ररूप तथा निधि का लेखा रित्या, स्थिरीकरण तथा परिसमापन सहायता निधि के लेखों का रखरखाव करेगा। उक्त निधि के लिये रखे गये तथा लेखा-परीक्षा। लेखों की लेखा-परीक्षा, विनियामक बोर्ड द्वारा नियुक्त लेखा-परीक्षक द्वारा किया जायेगा।

१४४-३१क. (१) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, अ-कृषिक सहकारी साख संस्था द्वारा १४४-५क, धारा १४४-९क, धारा १४४-१०क या, यथास्थिति, धारा १४४-२४क में निर्देशित बातों का उल्लंघन या चूक होती है तब, रजिस्ट्रार, ऐसी अ-कृषिक सहकारी साख संस्था पर अधिरोपित कर सकेगा,—

शास्ति अधिरोपित करने की रजिस्ट्रार की शक्ति।

(क) जहाँ उल्लंघन, धारा १४४-५क या धारा १४४-२४क में निर्देशित स्वरूप का है, वहाँ जिसके लिये ऐसा उल्लंघन किया गया है, संबंध, में, निक्षेप की रकम की दुगनी से अनधिक शास्ति होगी ;

(ख) जहाँ धारा १४४-९क की उप-धारा (१) या धारा १४४-१०क में निर्देशित स्वरूप के उल्लंघन या चूक हो, वहाँ पचास हजार रुपये से अनधिक या ऐसे उल्लंघन या चूक में, जहाँ ऐसी रकम परिमाणित है, में अंतर्ग्रस्त रकम से दुगनी, जो भी अधिक हैं, की शास्ति ;और जहाँ ऐसा उल्लंघन या चूक दुबारा होती है, प्रथम बार के पश्चात्, प्रतिदिन के लिये जब तक उल्लंघन की शास्ति निरंतर रहे, तब पच्चीस हजार रुपयों तक अधिकतर शास्ति विस्तारित की जायेगी।

(२) उप-धारा (१) के अधीन शास्ति के न्यायनिर्णय के प्रयोजन के लिये, रजिस्ट्रार, अ-कृषिक सहकारी साख संस्था को, सूचना में विनिर्दिष्ट रकम क्यों अधिकथित नहीं की गई के कारण बतानेवाली सूचना तामिल करेगा और सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर भी ऐसी अ-कृषिक सहकारी साख संस्था को दिया जायेगा।

(३) इस धारा के अधीन, रजिस्ट्रार द्वारा अधिरोपित शास्ति, रजिस्ट्रार द्वारा, अ-कृषिक सहकारी साख संस्था पर तामिल किये गये रकम के भुगतान की माँग करने वाली सूचना के जारी किये गये दिनांक से चौदह दिनों की अवधि के भीतर, भुगतानयोग्य होगा और ऐसी अवधि के भीतर, रकम के भुगतान करने में अ-कृषिक सहकारी साख संस्था के विफल होने की दशा में, यदि ऐसा जुर्माना मजिस्ट्रेट द्वारा स्वयं से, अधिरोपित किया गया है तो, मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित जुर्माने की वसूली के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ द्वारा उपबंधित रित्या वसूल किया जा सकेगा। वसूली पर, ऐसा जुर्माना, स्थिरीकरण तथा परिसमापन सहायता निधि में जमा किया जायेगा। ” ।

३. मूल अधिनियम की धारा १४६ के, खण्ड (त) के पश्चात्, निम्न खण्ड निविष्ट किये जायेंगे, सन् १९६१ का अर्थात् :— महा. २४ की धारा १४६ में संशोधन।

“ (त-१) अ-कृषिक सहकारी साख संस्था के मामले में, उपरोक्त के अतिरिक्त में,—

(एक) संस्था धारा ४३ या ४४ का उल्लंघन करती है ; या

(दोन) संस्था, धारा १४४-४क की उप-धारा (१) में निर्देशित से अन्य व्यवसाय के किन्हीं अन्य प्ररूप से जुड़ी है ; या

(तीन) संस्था, किसी गतिविधि में लगी है, जो धारा १४४-६क के उपबंधों के अनुसार प्रतिषिद्ध है ; या

(चार) संस्था, धारा १४४-७क में उल्लिखित उनुबद्ध अवधि के भीतर, संस्था को आवश्यक नहीं ऐसी संपत्ति का निपटान नहीं करती ; या

(पाँच) संस्था, धारा १४४-८क के अनुसार, यथा अधिसूचित प्रशासनिक तथा स्थापना के व्यय की सीमा से आगे बढ़ती हैं ;

(छह) संस्था, धारा १४४-११क तथा धारा १४४-१२क के उपबंधों के प्रतिकूल व्यवहार करती हैं ; या

(सात) संस्था, धारा १४४-२२क के अधीन जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों और विरचित विनियमों का अनुपालन करने में विफल होती हैं ; या

(आठ) संस्था, धारा १४४-२६क के उपबंधों के अनुसार, स्थिरीकरण तथा परिसमापन सहायता निधि की ओर अंशदान करने में विफल होती है ; या ”।

सन् १९६१ का
महा. २४ की धारा
१४७ में संशोधन।

४. मूल अधिनियम की धारा १४७ के, खण्ड (त) के पश्चात्, निम्न खण्ड, निविष्ट किये जायेंगे, अर्थात् :—

“ (त-१) यदि यह उस धारा के खण्ड (त-१) के अधीन अपराध है, तब पच्चीस हजार रुपयों तक बढ़ाए जा सकने वाले जुर्माने से, या तीन वर्षों तक बढ़ाये जा सके ऐसे कारावास से, या दोनों से दण्डित किया जायेगा ; ”।

(यथार्थ अनुवाद),

हर्षवर्धन जाधव,

भाषा संचालक,

महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. LVIII OF 2017.

**THE MAHARASHTRA PREVENTION OF FRAGMENTATION AND
CONSOLIDATION OF HOLDINGS (AMENDMENT) ACT, 2017.**

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक ६ सितम्बर, २०१७ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

नि. ज. जमादार,
प्रधान सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. LVIII OF 2017.

**AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA PREVENTION
OF FRAGMENTATION AND CONSOLIDATION OF HOLDINGS ACT.**

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५८, सन् २०१७।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, “महाराष्ट्र राजपत्र” में दिनांक ७ सितम्बर, २०१७ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

**महाराष्ट्र धृति के खण्डकरण और समेकन की रोकथाम अधिनियम में अधिकतर
संशोधन करने संबंधी अधिनियम।**

सन् १९४७ का ६२। **क्योंकि** इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र धृति का खण्डकरण और समेकन की रोकथाम अधिनियम में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर हैं ; इसलिए, भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में, एतद्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है, अर्थात् :—

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र धृति का खण्डकरण और समेकन की रोकथाम (संशोधन) अधिनियम, २०१७ संक्षिप्त नाम। कहलाए।

सन् १९४७ का ६२। २. महाराष्ट्र धृति का खण्डकरण और समेकन की रोकथाम अधिनियम की धारा ९ की, उप-धारा (३) के पश्चात्, निम्न परंतुक और स्पष्टीकरण, जोड़े जायेंगे, अर्थात् :— सन् १९४७ का ६२ की धारा ९ में संशोधन।

“ परंतु, धारा ३१ में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, कलक्टर, इस संबंध में किये गये आवेदन पर, यदि ऐसी भूमि, प्रचलित प्रारूप या अंतिम प्रादेशिक योजना में, आवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक या अर्ध-सार्वजनिक या किन्हीं अ-कृषिक उपयोग के लिये आंबटित की गई हैं या किसी वास्तविक अ-कृषक उपयोगकर्ता के लिये उपयोग किये जाने के लिये आशयिक हैं, तब, सरकार, समय-समय से, राजपत्र में अधिसूचित करें, ऐसे दरों के वार्षिक विवरण के अनुसार, ऐसी भूमि के बाजार मूल्य के २५ प्रतिशत से अधिक न हो ऐसे प्रतिशत पर विनियमिकरण अधिमूल्य के भुगतान के अध्यक्षीन, १५ नवंबर १९६५ को या के पश्चात् और धृति का खण्डकरण और समेकन की रोकथाम (संशोधन) अधिनियम, २०१७ के प्रारंभण के दिनांक से पूर्व बनाये गये इस अधिनियम के उपबंधों के सामने भूमि के अंतरण या विभाजन को विनियमित कर सकेगा :

परंतु, आगे यह कि, धारा ३१ में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यदि इस अधिनियम के उपबंधों के सामने भूमि के अंतरण या विभाजन का संव्यवहार, भूमि के किन्हीं **वास्तविक** अ-कृषक उपयोग के लिये उपयोग की जायेगी, के आधार पर, विनियमित हुआ है, तब, विनियमिकरण के दिनांक से ५ वर्षों के भीतर ऐसे **वास्तविक** अ-कृषक उपयोग शुरू करने में विफल होने के परिणामस्वरूप, कलक्टर द्वारा ऐसी भूमि का समपहरण किया जायेगा। तत्पश्चात्, ऐसी भूमि, पहले धारक या निकटवर्ती पड़ोसी का सर्वेक्षण क्रमांक या मान्यताप्राप्त उप-विभाजन सर्वेक्षण क्रमांक अधिभोगी को, विद्यमान दरों के वार्षिक विवरण के अनुसार, ऐसी भूमि के बाजार मूल्य के ५० प्रतिशत के भुगतान पर प्रस्तुत की जायेगी और इस प्रकार संग्रहीत की गई रकम की तीन-चौथाई रकम का, चूककर्ता व्यक्ति को, जिससे ऐसी भूमि सरकार को समपहित की गई थी, भुगतान किया जायेगा और इस प्रकार संग्रहीत रकम को शेष एक-चौथाई, सरकार के खाते में जमा की जायेगी। जब ऐसे निकटवर्ती पड़ोसी का सर्वेक्षण क्रमांक या मान्यताप्राप्त उप-विभाजन अधिभोगी खण्ड (टुकड़ा) खरीदने से मना करता है, तब खण्ड (टुकड़ा) की राज्य सरकार द्वारा नीलामी की जायेगी और उसके द्वारा प्राप्त आय चूककर्ता व्यक्ति और सरकार के बीच, ३:१ अनुपात में विभाजित की जायेगी।

स्पष्टीकरण.—इस उप-धारा के प्रयोजन के लिये, ‘दरों के वार्षिक विवरण’ का तात्पर्य, वर्ष जिसमें, कलक्टर द्वारा विनियमिकरण का आदेश जारी किया है या वर्ष, जिसमें से अधिमूल्य का भुगतान किया गया है, जो भी बाद में हो, के संबंध में प्रचलित, बॉम्बे स्टाम्प (संपत्ति के सही बाजार मूल्य का अवधारण) नियम, १९९५ या इस संबंध में तत्समय प्रवृत्त किन्हीं अन्य नियमों के उपबंधों के अधीन प्रकाशित दरों के वार्षिक विवरण, से है।”

(यथार्थ अनुवाद),

हर्षवर्धन जाधव,

भाषा संचालक,

महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. LIX OF 2017.

THE MAHARASHTRA STAMP (SECOND AMENDMENT) ACT, 2017.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक ६ सितम्बर, २०१७ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

नि. ज. जमादार,
प्रधान सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. LIX OF 2017.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA STAMP ACT.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५९, सन् २०१७।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, “महाराष्ट्र राजपत्र” में दिनांक ७ सितम्बर, २०१७ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम।

सन् १९५८ का ६०। **क्योंकि** इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर हैं ; इसलिए, भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में, एतद्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र स्टाम्प (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१७ कहलाए।

संक्षिप्त नाम।

सन् १९५८ का ६०। २. महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम को संलग्नित **अनुसूची एक** के,—

सन् १९५८ का ६० की अनुसूची एक में संशोधन।

(क) अनुच्छेद २५ के, खण्ड (ख) के—

(एक) उप-खण्ड (२) के, स्तंभ २ में, “ ४ प्रतिशत ” अंक और शब्द के स्थान में, “ ५ प्रतिशत ” अंक और शब्द रखा जायेगा ;

(दो) उप-खण्ड (तीन) के, स्तंभ २ में, “ ३ प्रतिशत ” अंक और शब्द के स्थान में, “ ४ प्रतिशत ” अंक और शब्द रखा जायेगा ;

(ख) अनुच्छेद ३४ के, खण्ड २ के परंतुक में,—

(एक) “ इस अनुच्छेद में यथा विनिर्दिष्ट समान दर पर या बाजार मूल्य पर प्रत्येक पाँच सौ रुपये या उसके भाग के लिये दस रुपये के दर पर ” शब्द के स्थान में, “ बाजार मूल्य के ३ प्रतिशत दर पर ” शब्द रखे जायेंगे ;

(दो) “ जो भी कोई कम हो ” शब्द अपमार्जित किये जायेंगे।

(यथार्थ अनुवाद),

हर्षवर्धन जाधव,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. LX OF 2017.**THE MAHARASHTRA LAND REVENUE CODE (THIRD AMENDMENT) ACT, 2017.**

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक ६ सितम्बर, २०१७ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

नि. ज. जमादार,
प्रधान सचिव एवं विधि परामर्शी,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. LX OF 2017.**AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA LAND REVENUE CODE, 1966.****महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६०, सन् २०१७।**

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, “महाराष्ट्र राजपत्र” में दिनांक ७ सितम्बर, २०१७ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

सन् १९६६ का
महा. ४१ का
४१।

संक्षिप्त नाम।

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र भू-राजस्व (तृतीय संशोधन) अधिनियम, २०१७ कहलाए।

सन् १९६६ का
महा. ४१ की धारा
१३५ की
प्रतिस्थापना।

२. महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ की धारा १३५ के स्थान में, निम्न धारा रखी जायेगी,
अर्थात् :—
सन् १९६६ का
महा. ४१ का
४१।

गाँवों, सर्वेक्षण
क्रमांक, और उप-
विभाजन या
किन्हीं सर्वेक्षण
क्रमांक या उप-
विभाजन के क्षेत्र
के बीच की
सीमाओं, के संबंध
में विवाद।

“ १३५. गाँव या क्षेत्र की सीमाओं या धृति, सर्वेक्षण नहीं हुआ है के संबंध में यदि कोई विविध उद्भूत होता है या यदि, सर्वेक्षण के पूरे होने के पश्चात्, किसी समय पर, किसी गाँव की सीमा, किसी सर्वेक्षण क्रमांक की सीमा या क्षेत्र या सर्वेक्षण क्रमांक के उप-विभाजन के संबंध में विवाद उद्भूत होता है, तब कलक्टर द्वारा, औपचारिक जाँच, जिसमें संबंधित अधिकारी और हित रखनेवाले सभी व्यक्तियों को उपस्थित होने और सबूत प्रस्तुत करने का अवसर होगा, के पश्चात्, विनिश्चित किया जायेगा। कलक्टर, ऐसे विवाद के निपटाने के समय या अन्यथा, सभी संबंधित व्यक्तियों और अधिकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, सर्वेक्षण की गलती या गणितीय अशुद्ध गणना के कारण सर्वेक्षक क्रमांक या उप-विभाजन के क्षेत्र या निर्धारण में किसी त्रुटि को भी सुधार सकेगा :

परंतु, भू-राजस्व का कोई बकाया, ऐसे सुधार के कारण द्वारा भुगतान योग्य नहीं होगा ; किंतु भू-राजस्व के रूप में किया गया अधिकतर भुगतान, यदि कोई हो, भू-राजस्व, जो देय होगा के सामने समायोजित किया जायेगा। ”।

(यथार्थ अनुवाद),

हर्षवर्धन जाधव,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।